मोदी सरकार

4 साल विकास के...
... संकल्प और विश्वास के

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

श्री राधा मोहन सिंह
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

श्री परशोत्तम रूपाला
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री

श्रीमती कृष्णा राज
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री

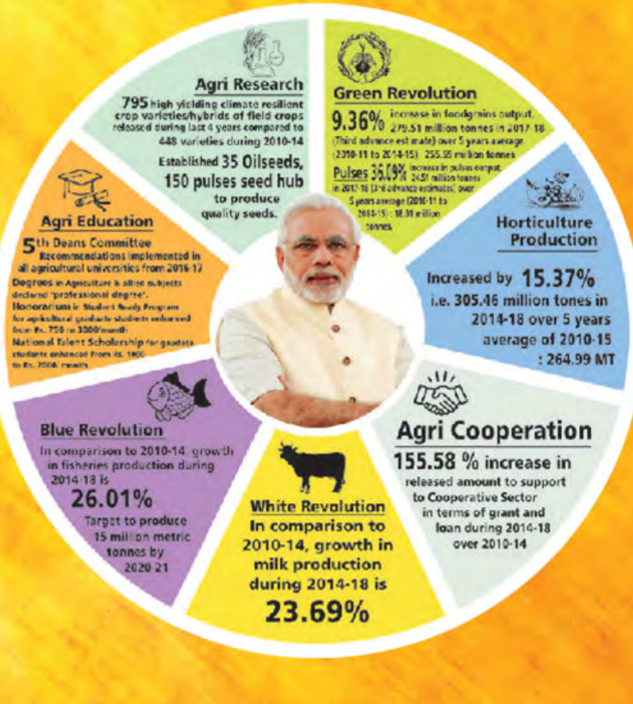

Agri Research
795 high yielding climate resilient crop varieties/hybrids of field crops released during last 4 years compared to 448 varieties during 2010-14
Established 35 Oilseeds, 150 pulses seed hub to produce quality seeds.
Green Revolution
9.36% increase in foodgrains output. 279.51 million tonnes in 2017-18 (Third advance estimate) over 5 years average (2010-11 to 2014-15) : 255.59 million tonnes
Pulses 36.09% increase in pulses output
Horticulture Production
Increased by 15.37% i.e. 305.46 million tones in 2014-18 over 5 years average of 2010-15 : 264.99 MT
Agri Cooperation
155.58 % increase in released amount to support to Cooperative Sector in terms of grant and loan during 2014-18 over 2010-14
White Revolution
In comparison to 2010-14, growth in milk production during 2014-18 is
23.69%
Blue Revolution
In comparison to 2010-14, growth in fisheries production during 2014-18 is
26.01%
Target to produce 15 million metric tonnes by 2020 21
Agri Education
5th Deans Committee Recommendations implemented in all agricultural universities from 2016-17
Degrees in Agriculture & allied subjects declared "professional degree".
National Talent Scholarship for graduate students

खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन (2017–18)

2017–18 का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 वर्ष (2010–11 से 2014–15) के औसत से 9.35 प्रतिशत से अधिक है।

मोदी सरकार द्वारा बजटीय आवंटन अधिक किया गया

बजटीय आवंटन के अलावा कॉर्पस फंड का प्रावधान :

- सूक्ष्म सिंचाई परियोजना–रु. 5,000 करोड़ (वर्ष 2017–18)
- डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (DIDF)–रु. 10,881 करोड़

वर्ष 2018–19 में घोषित

- कृषि बाजार अवसंरचना विकास कोष–रु. 2,000 करोड़
- मत्स्य एवं जलजीव विज्ञान अवसंरचना विकास कोष–रु. 2,450 करोड़
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष–रु. 7,550 करोड़

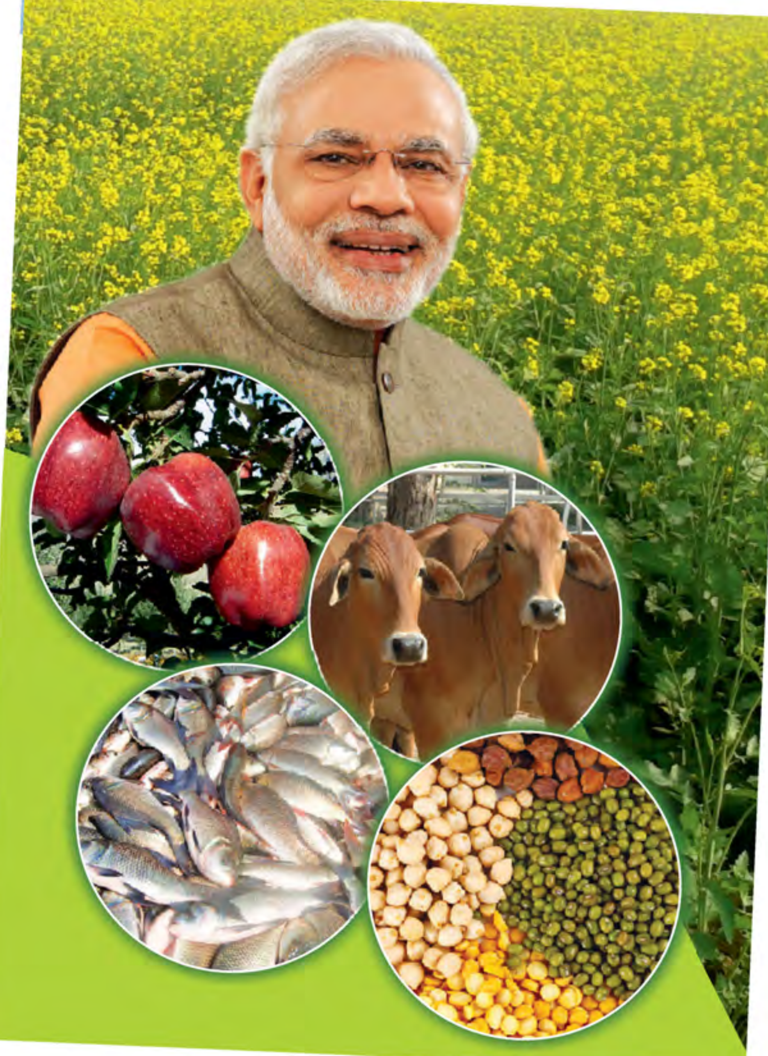

मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन

सॉयल हैल्थ कार्ड का वितरण

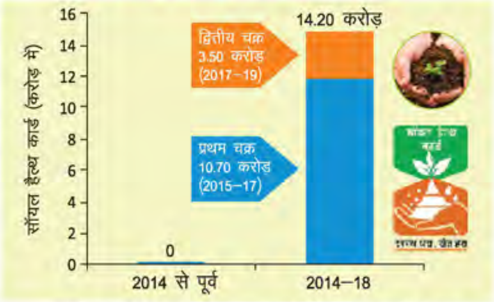

मार्च 2018 तक प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में कुल 14.20 करोड़ से ज्यादा सॉयल हैल्थ कार्ड वितरित किए गए।

मंजूर की गई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (अचल+चल+मिनी–प्रयोगाशालाएं)

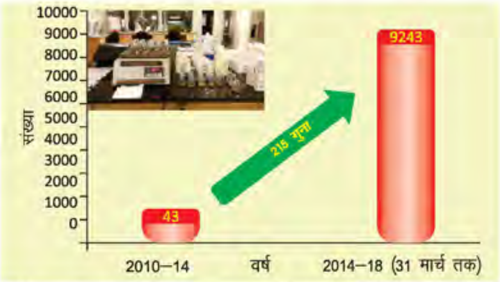

वर्ष 2010–14 में केवल 43 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं थी जो बढ़कर वर्ष 2014–18 में 9243 हो गयी।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत जारी की गई धनराशि

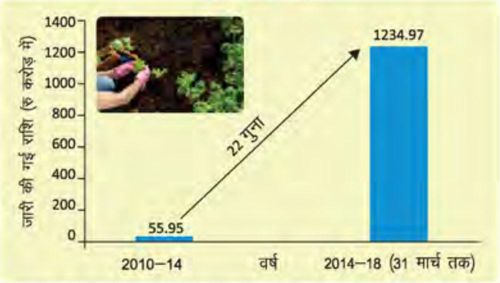

वर्ष 2010–14 में राज्यों को जारी रुपये 55.95 करोड़ की राशि के मुकाबले वर्ष 2014–18 में रुपये 1234.97 करोड़ जारी, इसमें 22 गुना वृद्वि हुई है।

जैविक खेती के विकास के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना : क्लस्टरों की संख्या

परंपरागत कृषि विकास योजना केन्द्र सरकार की पहली व्यापक योजना है। अब तक 10,000 समूहों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है।

परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि

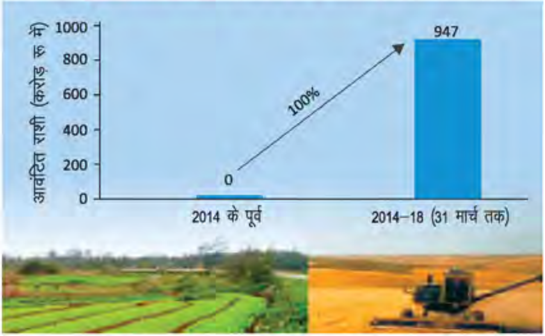

परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चार वर्षों में आवंटित राशि रुपये 947 करोड़ वितरित की गई

मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–18 के दौरान निर्मुक्त राशि

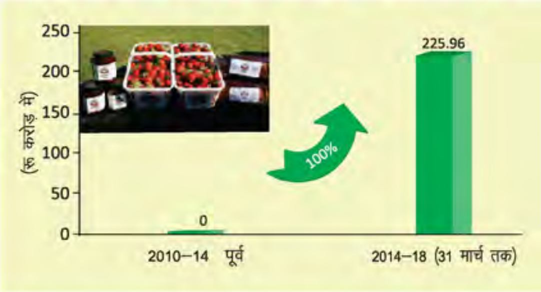

वर्ष 2014–18 के दौरान एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत बज़ट में भारी वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) के अंतर्गत प्रगति

- वर्ष 2018–19 में 200 अतिरिक्त मंडियों को भी ई–नाम से जोड़ा जायेगा
- देश के लगभग 22,000 ग्रामीण कृषि मण्डियों के विकास के लिए नावार्ड ने रुपये 2000 करोड़ राशि प्रस्तावित की है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) के अंतर्गत व्यापार

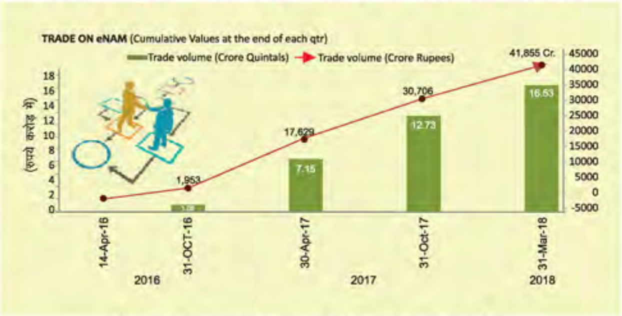

ई–नाम के अन्तर्गत व्यापार में सतत वृद्धि हुई है

फसल बीमा योजना के तहत शामिल किसान

खरीफ मौसम

2010–14 खरीफ मौसम की तुलना में 2014–18 में ऋृणी व गैर ऋणी किसानों के कुल व्याप्ति में 63.68 प्रतिशत की वृद्वि। उल्लेखनीय है कि गैर ऋणी किसानों के व्याप्ति में 173.17 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

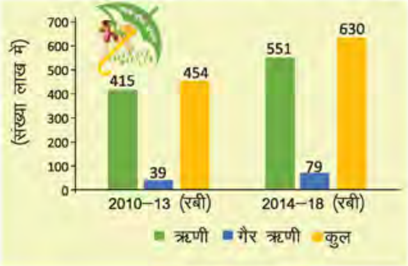

रबी मौसम

2010–14 रबी मौसम की तुलना में 2014–18 में ऋृणी व गैर ऋणी किसानों के कुल व्याप्ति में 38.76 प्रतिशत की वृद्वि। उल्लेखनीय है कि गैर ऋणी किसानों के व्याप्ति में 102.56 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

वर्ष 2013–14 (सामान्य वर्ष) के सापेक्ष वर्ष 2016–17 (आपदा वर्ष) के दौरान बीमित किसानों के प्रति हैक्टेयर दावों की तुलना

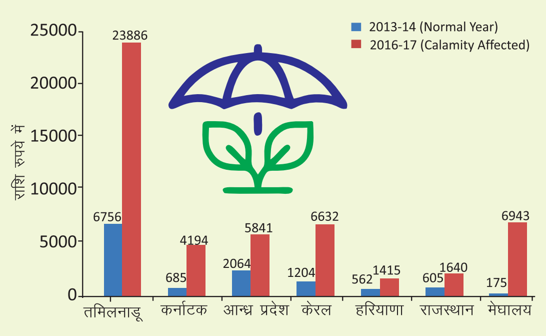

पुरानी योजनाओं की तुलना में पीएमएफबीवाई के तहत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि में वृद्धि

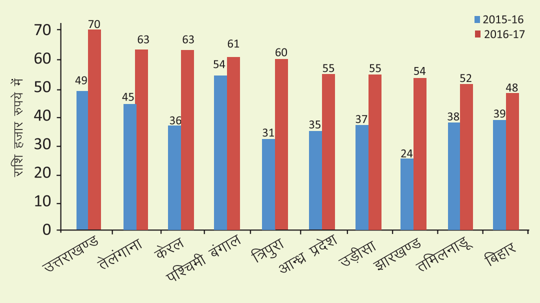

सूक्ष्म सिंचाई हेतु जारी की गई राशि

वर्ष 2010–14 के दौरान 4698.65 करोड़ रु. की राशि दी गई, वहीं 2014–18 (31 मार्च 2018 तक) के दौरान 5460.12 करोड़ रु. अतिरिक्त राशि दी गई है जो 16.21% ज्यादा है।

माइक्रो इरीगेशन के तहत क्षेत्र

(अब तक का सर्वाधिक क्षेत्रफल)

वर्ष 2010–14 की तुलना में वर्ष 2014–18 तक माइक्रो इरीगेशन में 24.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

वर्ष 2010–14 एवं 2014–18 के दौरान एमआईडीएच के प्रमुख घटक के तहत उपलब्धियां

वर्ष 2014–18 के दौरान एमआईडीएच के प्रमुख घटकों में विशेष उपलब्धियां हांसिल की गई है।

शीत भण्डारण योजना में प्रगति

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने पूरे देश में 3120 शीत भंडारण परियोजनाओं को सहायता दी जिनकी कुल भंडारण क्षमता 137.22 लाख मी. टन है।

व्यावसायिक बागवानी योजना

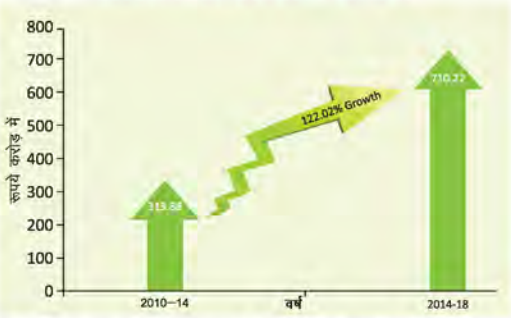

व्यवसायिक बागवानी योजनाओं में पिछले 4 सालों में आवंटित राशि में 122.02 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

बागवानी फसलों में रिकॉर्ड पैदावार

भारत सरकार के बागवानी विकास के लिए किए गए प्रयासों के वजह से पिछले चार सालों में बागवानी फसलों के उत्पादनों में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई है।

नारियल विकास के विभिन्न संघटकों में उपलब्धि

नारियल विकास के विभिन्न संघटकों में नारियल विकास बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गयी है।

नारियल उत्पादक समिति, फैडरेशन तथा नारियल उत्पादक कम्पनी

पिछले वर्षों में नारियल उत्पादक समिति, फैडरेशन तथा नारियल उत्पादक कम्पनीयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जारी/आवंटित निधियां

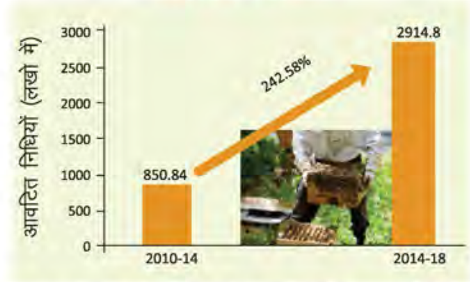

वर्ष 2010–14 की तुलना में पिछले चार वर्षों (2014–18) में मधुमक्खी पालन के लिए आवंटित बजट में लगभग 242.58% की वृद्धि हुई है।

कुल शहद उत्पादन

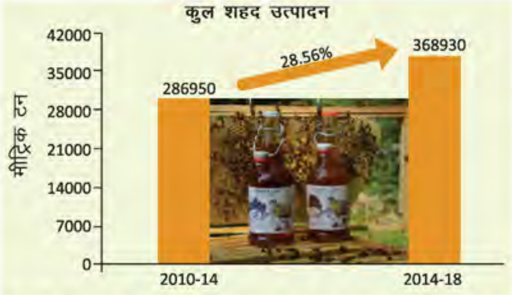

राष्ट्रीय बी बोर्ड द्वारा मधुमक्खी पालकों/किसानों को सहायता देने के कारण शहद उत्पादन में वर्ष 2010–14 की तुलना में पिछले चार वर्षों (2014–18) में 28.56% की वृद्धि।

दलहन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी (मिलियन टन)

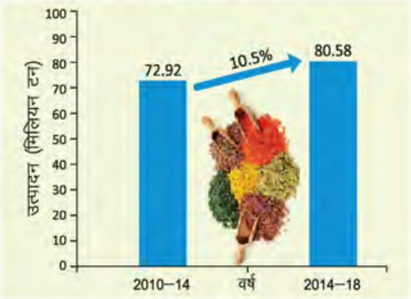

दहलन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की बजह से वर्ष 2016–17 व 2017–18 में क्रमशः 23.13 व 23.95 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन

पूर्वी राज्यों में धान के पड़ती क्षेत्रों में तिलहनों और दालों को बढ़ावा

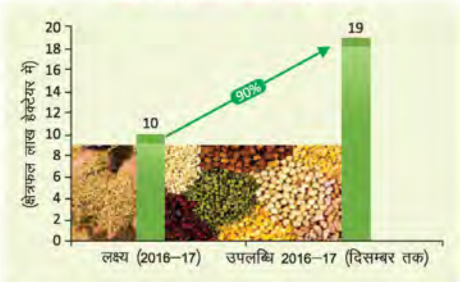

पूर्वी राज्यों में धान के परती क्षेत्रों में तिलहनों और दालों के क्षेत्र में 90 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

ऑयल पाम विकास के लिए विभिन्न घटकों में सहायता में बढ़ोतरी

ऑयल पाम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

बीज प्रभाग की पहलें एवं उपलब्धियां

भारत सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक रही।

राष्ट्रीय बीज निगम के कारोबार में वृद्धि

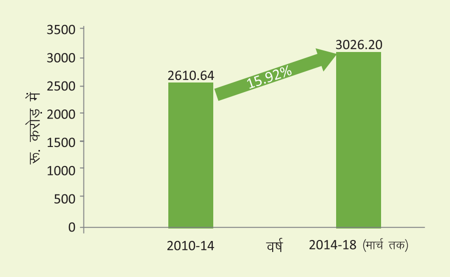

पिछले वर्षो (2010–14) की तुलना में विभिन्न फसलों और सब्जियों के बीज की बिक्री में वृद्धि होने से गत 4 वर्षों (2014–18) में कारोबार में 15.92% वृद्धि हुई।

बीज भंडारण क्षमता में तुलनात्मक बढ़ोत्तरी

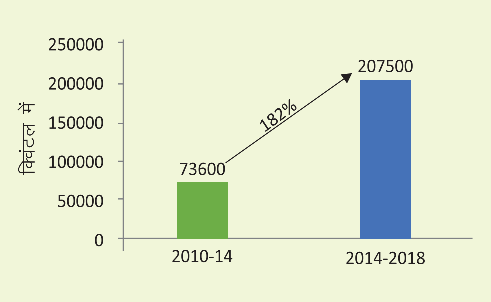

वर्ष 2010–14 की तुलना में वर्ष 2014–18 में भंडारण क्षमता में 182% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे बीज की मात्रा बढ़ी तथा इसका स्थानान्तरण का खर्चा घटा।

एनएससी द्वारा जुताई क्षेत्र के अन्तर्गत बढ़ोत्तरी

वर्ष 2010–14 की तुलना में वर्ष 2014–18 में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत जुताई क्षेत्र में 358.33% की बढ़ोत्तरी हुई।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा मछली के बीज उत्पादन

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा मछली के बीज उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा दिया गया लाभांश

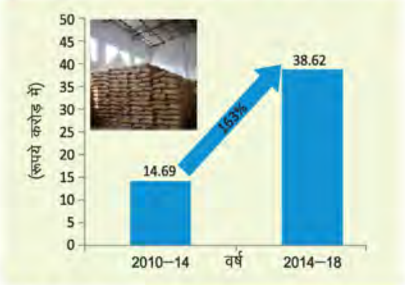

राष्ट्रीय बीज निगम के लाभांश में 2010–14 की तुलना में वर्ष 2014–2018 के दौरान 163 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

धान की एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट किस्मों के बीज की पैदावार

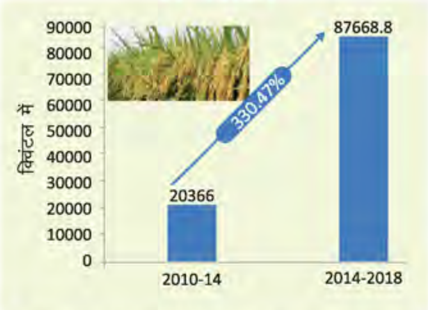

वर्ष 2010–14 की तुलना में वर्ष 2014–18 के दौरान धान की एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट किस्मों के बीज के उत्पादन में 330.47 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

2007 से 2018 तक 150 फसलें (प्रजातियां) अधिसूचित की गई।

आवेदन प्राप्त करने तथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने में उपलब्धियाँ

कृषक किस्मों के आवेदन प्राप्त करने तथा प्रमाण–पत्र जारी करने में उपलब्धियाँ

कृषि यंत्रीकरण

किसानों को वितरित मशीनों की संख्या

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2010–14 के दौरान वितरित मशीनों की संख्या की तुलना में वर्ष 2014–18 के दौरान किसानों को वितरित की गई मशीनों की संख्या में 153.64% की बढ़ोत्तरी हुई है।

आवंटित निधि

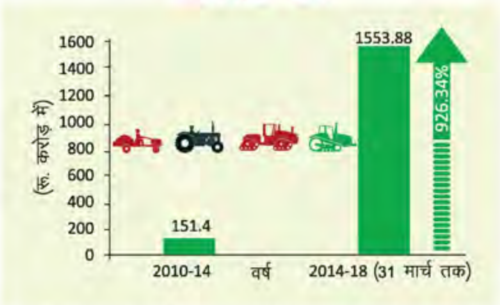

वर्ष 2010–14 के दौरान कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के लिए आवंटित निधि की तुलना में वर्ष 2014–18 में कुल 926.34% अधिक राशि आवंटित की गई।

पौध संरक्षण कीटनाशी निर्यात पंजीकरण

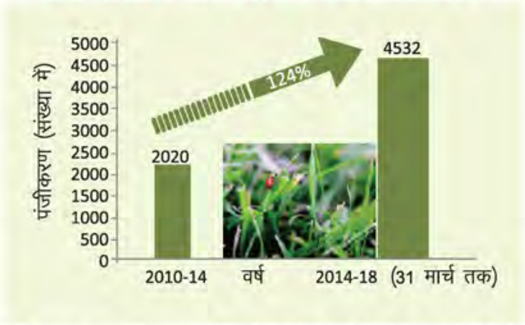

वर्ष 2010–14 की तुलना में वर्ष 2014–18 में कीटनाशी निर्यात पंजीकरण में 124% की बढ़ोत्तरी।

पौध संरक्षण कीटनाशी पंजीकरण

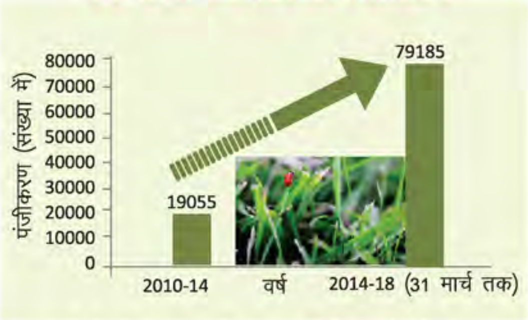

तकनीकों के उपयोग और उत्तम निरीक्षण से कीटनाशक पंजीकरण में 312% की बढ़ोत्तरी।

उद्यम पूंजी योजना (वी सी ए) के अन्तर्गत स्थापित की गईं परियोजनाएं

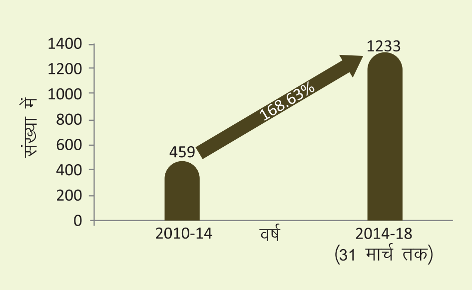

पिछले 4 वर्षों (2010–14) के दौरान 459 के मुकाबले 2014–18 के दौरान 1233 वीसीए परियोजनाएं स्थापित की गईं जो 168.63 प्रतिशत की वृद्धि है।

नाबार्ड एवं एसएफएसी द्वारा किसान उत्पादन संगठनों का पंजीकरण

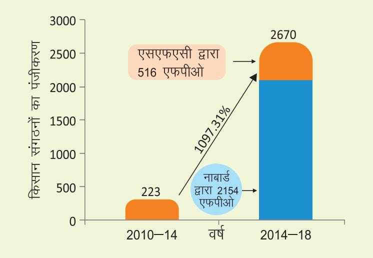

नाबार्ड (2154) व एसएफएसी (516) द्वारा वर्ष 2014–18 के दौरान 2617 किसान संगठनों का पंजीकरण करवाया गया। जो कि वर्ष 2010–14 (223) की अपेक्षा 1097 प्रतिशत अधिक है।

आधारभूत कृषि ऋण प्रवाह (अल्पकालिक फसल ऋण एवं सावधि ऋण)

वर्ष 2010–14 की तुलना में 2014–18 (फरवरी 2018 तक) के दौरान आधारभूत कृषि ऋण प्रवाह में 63% वृद्धि हुई।

कृषि ऋणः अल्पकालिक फसल ऋण

वर्ष 2010–14 की तुलना में वर्ष 2014–18 के दौरान 48% अल्पकालिक ऋण में वृद्धि हुई है।

ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप का गठन

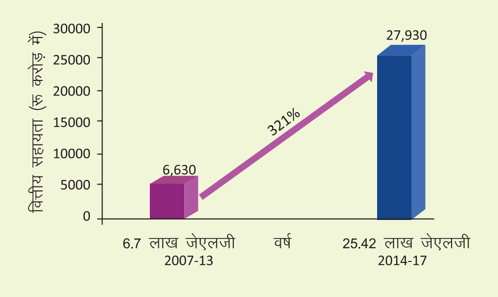

वर्ष 2007 से 2017 तक मात्र 6.72 लाख ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनाकर 7 वर्ष में रु. 6630 करोड़ की राशि दी गई जबकि 2014–17 साढ़े तीन वर्षों में 25.42 लाख ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनाकर रु. 27930 करोड़ राशि दी गई।

नेफेड के द्वारा खरीद से लाभान्वित कृषक

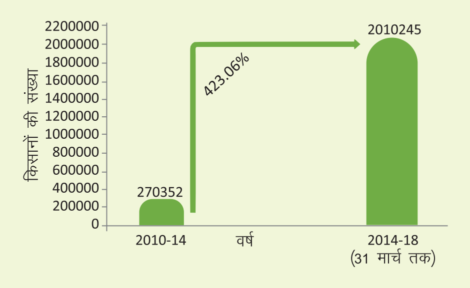

वर्ष 2010–14 के बीच 270352 किसान नाफेड द्वारा खरीद से लाभान्वित हुए। इसकी तुलना में वर्ष 2014–18 के दौरान 2010245 किसान लाभान्वित हुए जो कि 423.06% अधिक है।

नेफेड के व्यवसाय में वृद्धि

वर्ष 2010–14 में रुपये 3663.37 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014–18 के दौरान नेफेड के व्यवसाय में रुपये 6496 करोड़ की वृद्धि हुई जो 41.67% अधिक है।

कृषि वानिकी विकास के लिए जारी धन राशि (रु. लाख)

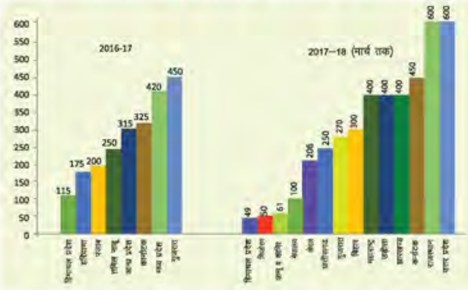

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गयी है।

राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए आवंटित धन राशि

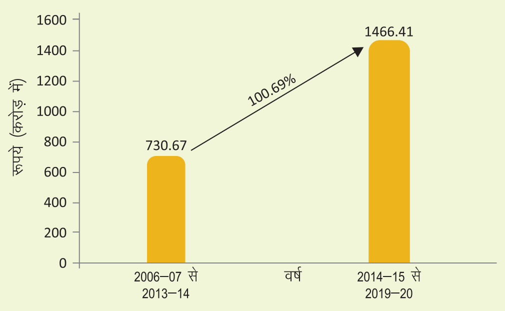

बांस के विकास के लिए 2014–15 से 2019–20 छः वर्ष की अवधि में रुपये 1466.41 करोड़ प्रस्तावित है। यह राशि 2006–07 से 2013–14 (8 वर्ष) की अवधी की तुलना में 104.15 प्रतिशत अधिक है।

राज्य आपदा अनुक्रिया कोष के अंतर्गत राज्यों को प्राकृतिक आपदा निधियों का आबंटन

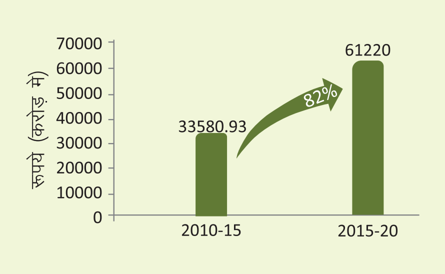

वर्ष 2010–2015 की तुलना में वर्ष 2015–20 में राज्यों को प्राकृतिक आपदा निधियों का आबंटन में 82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्राकृति आपदा (सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप एवं शीत लहर/पाला) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को अनुमोदित केन्द्रीय सहायता

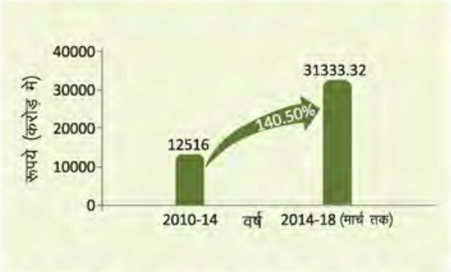

2010–2014 में स्वीकृत रुपये 12516 करोड की तुलना में 2014–18 में रुपये 31333.32 करोड की मंजूरी दी गई, जो कि 140.50 प्रतिशत अधिक है।

प्राकृति आपदा और एनडीआरएफ के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को अनुमोदित केन्द्रीय सहायता

सभी श्रेणी की सहायता मापदंड 1.5 गुना बढ़ाए गए है।

प्रमुख कृषि किस्मों का निर्यात (2010–14 से 2014–18)

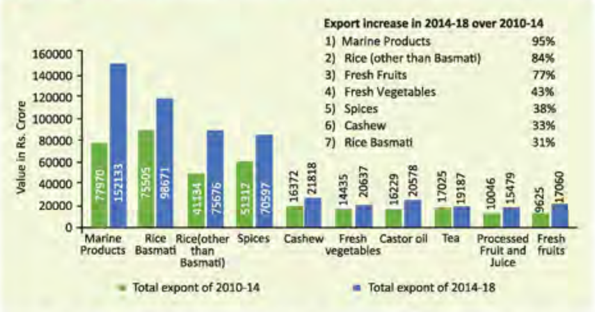

सरकार की निर्यातोन्मुखी नीतियों के कारण समुद्रीय उत्पाद, ताजे फलों सब्जियों चावल (गैर–बासमती), चावल (बासमती) व मसाले के निर्यात में वृद्धि हुई है।

एनसीडीसी द्वारा अभूतपूर्व निर्गमित राशि

एनसीडीसी द्वारा वर्ष 2010–14 में रुपये 19850.57 करोड़ राशि निर्गमित की गई है, वहीं वर्ष 2014–18 (मार्च तक) में यह 155.58% बढ़कर रुपये 50735.04 करोड़ हो गई है।

एसी और एबीसी योजना के अंतर्गत जारी धनराशि (रु. लाख में)

पिछले चार वर्ष के दौरान एसी और एबसी योजना को अधिक धन राशि आवंटित कर इसे बढ़ावा दिया गया है।

एसी और एबीसी योजना के तहत स्थापित उम्मीदवारों की वृद्धि दर (2010–14 से 2014–18)

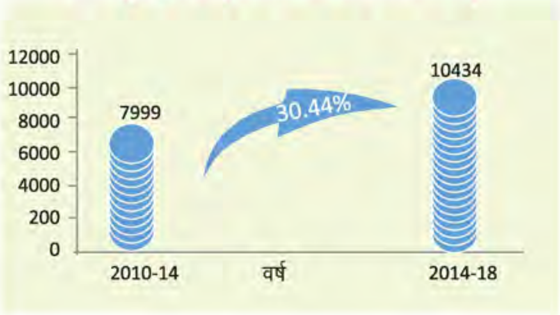

इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा के तहत प्रगति

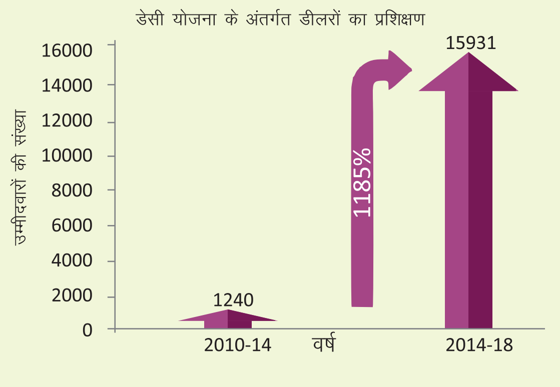

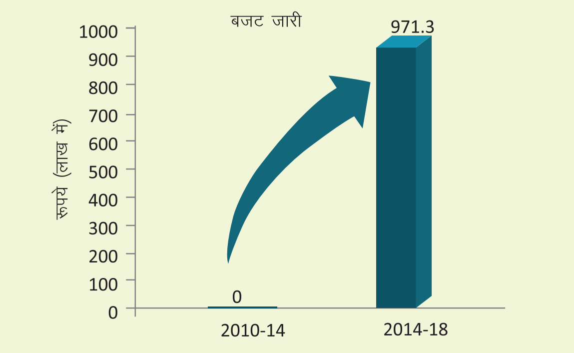

आत्मा योजना के अन्तर्गत प्रगति

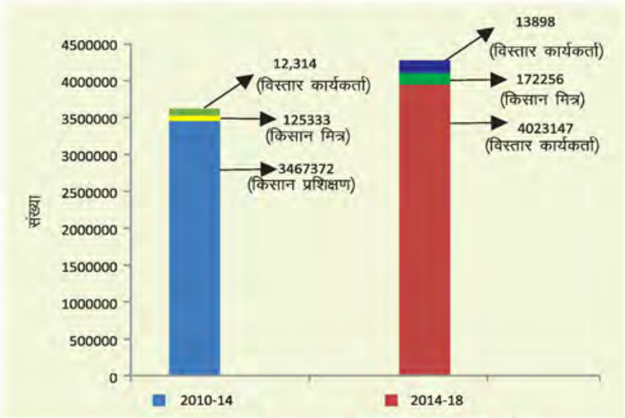

आत्मा योजना के अन्तर्गत आवंटित निधि

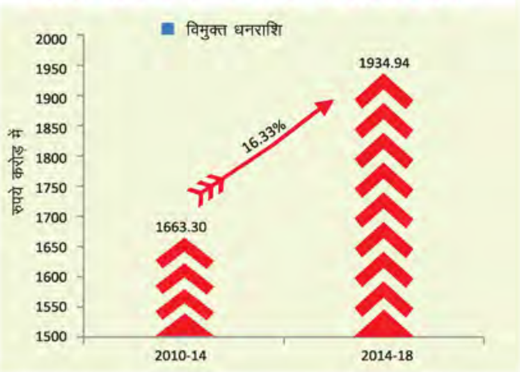

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजना

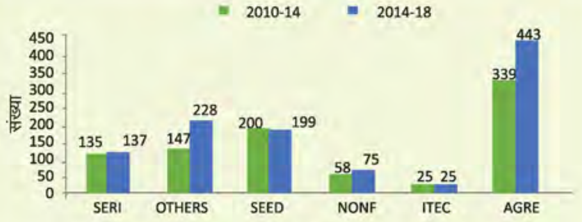

SERI = Sericulture, Other = Innovative Programme, NONF = Non Farm Activities, ITEC = Information Technology, AGRE = Agri/Horti/Animal Husbandary

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा राज्यों की विभिन्न परियोजना में वृद्वि दर्ज हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी-किसानों के लिए बनाए गए मोबाईल एप्स

किसान सुविधा मोबाइल ऐप

पूसा कृषि मोबाइल ऐप

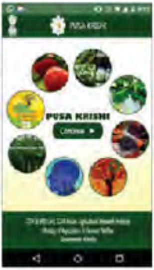

क्रॉप इन्स्योरेंस मोबाइल ऐप

सीसीई कृषि – मोबाइल एप

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत जारी की गई राशि

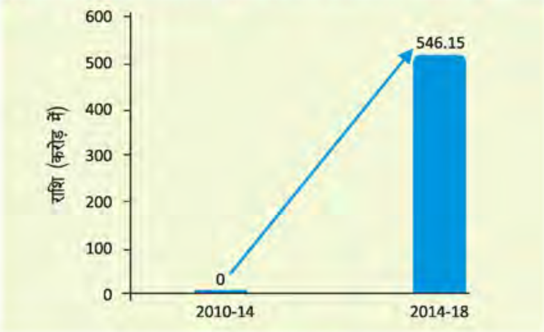

दुग्ध उत्पादन

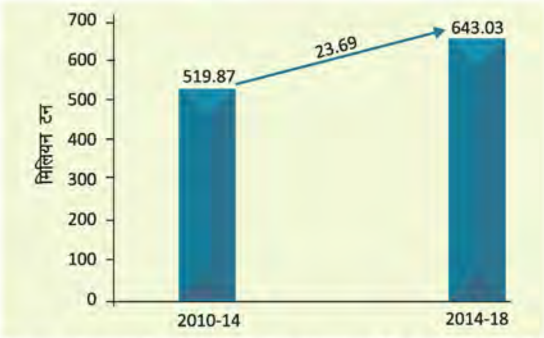

2010–14 के मुकाबले 2014–18 में दुग्ध उत्पादन वृद्धि 23.69 प्रतिशत है। (2017–18 का डाटा अभी राज्यों लंबित हैं अतः 2017–18 का प्रोजेक्टेड डाटा का प्रयोग किया गया है।)

किसानों को अदा की जाने वाली औसत कीमत में वृद्धि

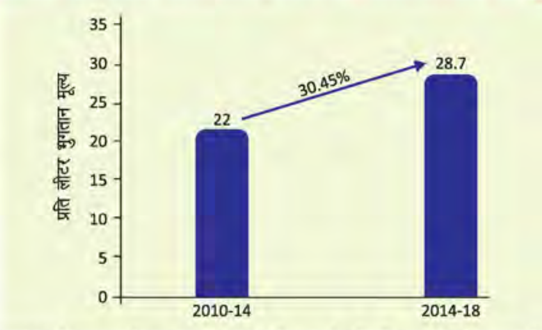

2010–14 के मुकाबले 2014–18 के दौरान डेयरी किसानों की आय में 30.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

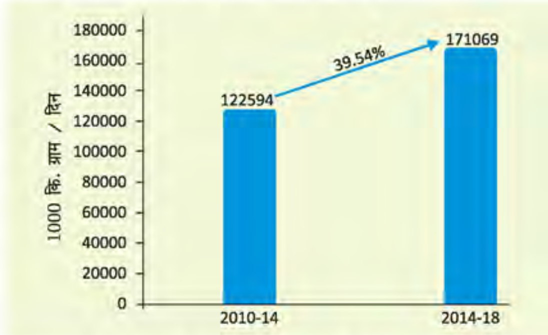

2010–14 के मुकाबले 2014–18 में डेयरी को–ऑपरेटिव द्वारा दूध खरीद में 39.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वीर्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि

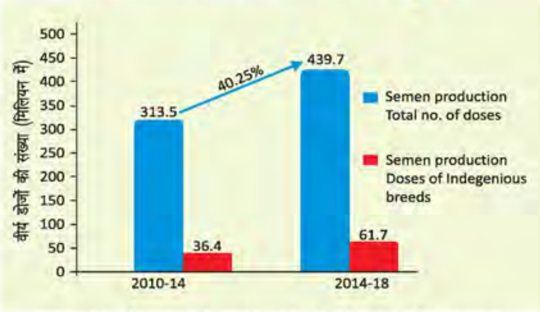

2010–14 के मुकाबले 2014–18 के दौरान वीर्य उत्पादन में 40.25 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

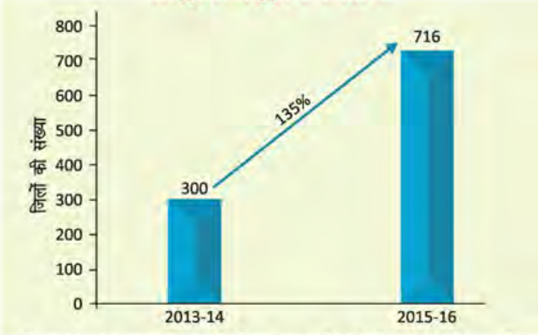

वर्ष 2013–14 तक पशुधन बीमा 300 जिलों में लागू थी जबकि 2016–17 में सभी 716 जिलों में लागू कर दिया गया है जो कि 135 प्रतिशत की वृद्धि है।

अंडा उत्पादन

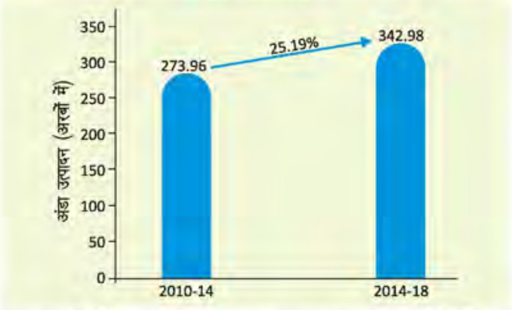

वर्ष 2010–14 के दौरान अंडा उत्पादन 273.96 अरब था जो कि 2014–18 में बढ़कर 342.98* अरब हो गया। अंडा उत्पादन में 25.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खुरपका और मुंहपका रोग के प्रकोप में कमी

खुरपका और मुंहपका प्रकोप जो 2010–13 के दौरान 2379 से घटकर 2014–17 के दौरान केवल 632 रह गये है। इसके प्रकोप में 73.43 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई है।

पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि

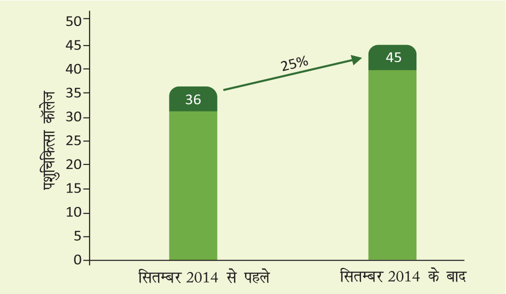

2011–14 की अवधि के दौरान पहली अनुसूची में कॉलेजों की संख्या 36 थी। 2014 से 2017 के दौरान पशुचिकित्सा कॉलेजों की कुल संख्या बढ़कर 45 हो गई है जो कि 25 प्रतिशत की वृद्धि है।

पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि

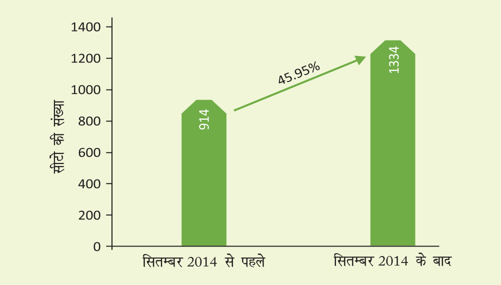

प्रशिक्षित पशुचिकित्सा श्रमशक्ति को पूरा करने के संबंध में, विभिन्न पशुचिकित्सा कॉलेजों में विद्यार्थियों की सीटें 60 से बढ़कर 100 हो गई थी। 17 पशुचिकित्सा कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या 914 से बढ़कर 1334 हो गई है जो कि 45.95 प्रतिशत की वृद्धि है।

मछली उत्पादन

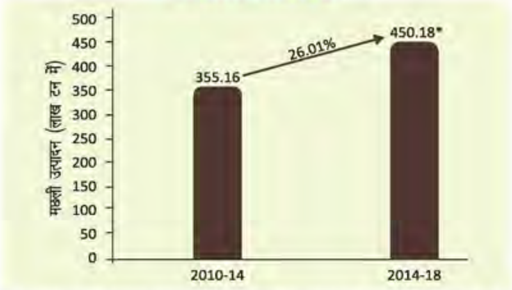

2010–14 के दौरान मछली उत्पादन 355.16 लाख टन था जो कि 2014–18 में बढ़कर 450.18* लाख टन हो गया है। इसमें 26.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मछुआरों के हितों के मद्देनजर बचत–सह–राहत राशि में वृद्धि

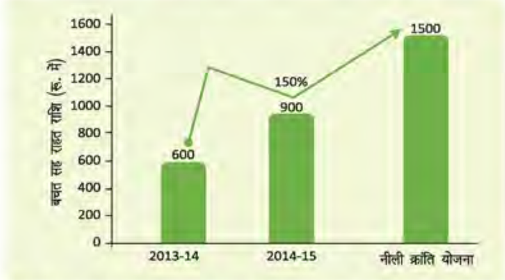

नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन के तहत 3 माह की मत्स्यन निषेध अवधि के दौरान बचत–सह–राहत की राशि में 150 प्रतिशत की वृद्धि करके मछुआरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मात्स्यिकी अवसंरचना विकास

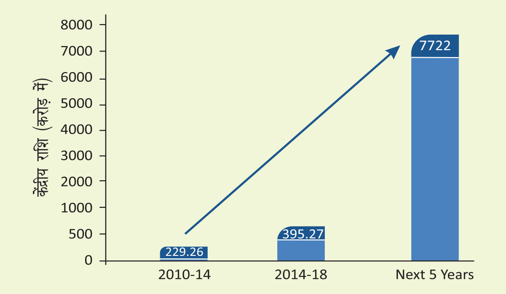

मात्स्यिकी अवसंरचना विकास हेतु जारी किए गए केन्द्रीय राशि में 72.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगले पांच वर्षों (2018–19 सहित) में अनुमानित व्यय 7722 करोड़ है जिसमे 7522 करोड़ मात्स्यिकी तथा जलकृषि अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत होगी।

सह निधियन के आधार चार नए बंदरगाहों का निर्माण तथा एक बंदरगाह का आधुनिकीकरण

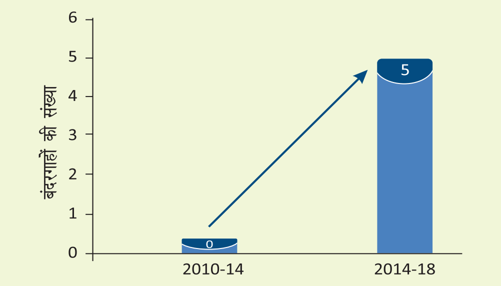

(नीली क्रांति और सागरमाला के अन्तर्गत परियोजनाएं)

भाकृअनुप
ICAR

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

मिश्रित खेती, खुशियों की खेती, समेकित कृषि प्रणाली विषय पर
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पहली झांकी,
69वी गणतन्त्र दिवस परेड, नई दिल्ली

महामहिम राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों एवं कलाकारों का सम्मान

राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना

वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2018–19 तक उच्चतर कृषि शिक्षा के क्षेत्र में बजटीय आबंटन में 55.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

कृषि विश्वविद्यालयों में खोली गई नई अनुभवजन्य शिक्षण इकाईयाँ

खोली गई नई अनुभवजन्य शिक्षण इकाईयाँ किसानों को प्रशिक्षण के साथ–साथ लाभ कमाने का वास्तविक अनुभव प्रदान कराती हैं।

स्टूडेन्ट रेडी

छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली अध्येतावृति में वृद्धि

छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली अध्येतावृति वर्ष 2016–17 से रुपये 750 प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 3000 प्रतिमाह की वृद्धि।

नए महाविद्यालयों की स्थापना हेतु न्यूनतम मानक

कृषि विज्ञान के विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने हेतु एवं उच्चतर कृषि शिक्षा हेतु नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए न्यूनतम मानक स्थापित किये गये।

कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

भारतीय संस्थानों की रैंकिंग पर की गई राष्ट्रीय पहल की तर्ज पर कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई। इस आधार पर किए मूल्यांकन द्वारा 57 कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग कर निम्नांकित विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए: 1. भाकृअप–डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल 2. भाकृअप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 3. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

स्नातक स्तर के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति में दो गुना वृद्धि

राशि को रु. 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 2000 प्रतिमाह किया गया (1351 लाभार्थी)

कृषि विश्वविद्यालयों की आधिकारिक मान्यता (Accreditation) पर बल

आधिकारिक मान्यता की प्रक्रिया को और वस्तुपरक बनाने हेतु भाकृअप ने "भारत में उच्चतर कृषि संबंधी शिक्षा संस्थानों की आधिकारिक मान्यता के लिए दिशा निर्देश" तैयार कर प्रकाशित किए हैं

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस

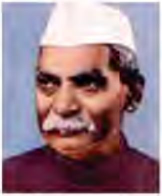

स्कूली छात्रों के बीच कृषि एवं कृषि संबंधी शिक्षा के बारे में जागरूकता सृजन करने हेतु प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्मृति में 3 दिसम्बर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस घोषित किया गया।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना

32 कृषि विश्व विद्यालयों में जैविक खेती/प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5.35 करोड़ रु. के बजट के साथ 100 केंद्रों की पहचान की गई। 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं व प्रशिक्षणों (लखनऊ, कोल्हापुर, अविकानगर, अमृतसर एवं झांसी) का आयोजन किया गया

नेताजी सुभाष–भाकृअप अंतर्राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित मानव संसाधनों का विकास किया गया (भारतीय छात्रों के लिए)–105 छात्र लाभान्वित। विदेशी छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों में प्रायोगिक प्रशिक्षण की सुविधा एवं कार्य करने का अनुभव प्रदान किया गया – 28 विदेशी छात्र लाभान्वित। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 30 छात्रवृतियों का प्रावधान किया गया है। विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को 2000 डॉलर प्रति माह एवं भारत आने वाले विदेशी छात्रों के लिए 40,000 रु. प्रति माह भाकृअप द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं।

भारतीय छात्रों का प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थानों में प्लेसमेंट

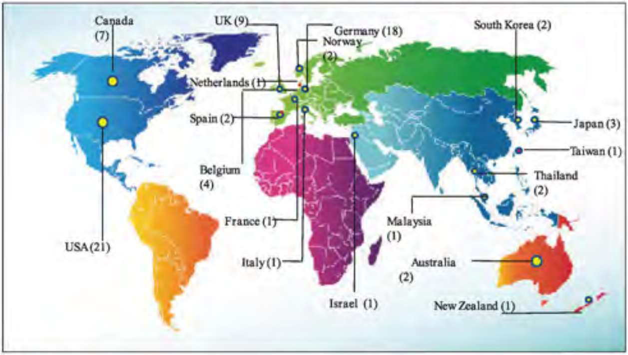

विदेशी छात्रों का प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थानों में प्लेसमेंट

उत्पादकता एवं आय बढ़ाने के लिए नई किस्में

वर्तमान 4 वर्षों (2014 से 2018) और इससे पहले के 4 वर्षों के दौरान (2010 से 2014) जारी की गई फसल किस्में

फसल सुधार में जैव तकनीकियों (Molecular breeding techniques) का उपयोग कर विकसित की गई किस्में

मई 2010 से अप्रैल 2014	मई 2014 से अप्रैल 2018
2 किस्में विकसित की गई हैं • पूसा बासमती 1 (धान) • एचबीबी 67 इमप्रूव्ड (बाजरा)	24 किस्में विकसित की गई हैं • धान की 19 किस्में • ब्रैड गेहूं की 1 किस्म • मक्का की 4 किस्में

कुपोषण से लड़ने के लिए पोषक तत्वों से समृद्ध फसलों की किस्मों का विकास

धानः सीआर धान 310ः प्रोटीन 10.3 प्रतिशत

धानः डीआरआर धान 45ः जिंक 22.6 पीपीएम

धानः जीएन आर–4ः अधिक आयरन (91 पीपीएम), आहार रेशे (2.87%) एवं बीटा – कैरोटीन (0.53पीपीएम)

धानः डीआरआर धान 48ः अधिक जिंक (22 पीपीएम)

धानः डीआरआर धान 49ः अधिक जिंक (25.2 पीपीएम)

गेहूंः डब्ल्यूबी 02 अधिक जिंक (42.0 पीपीएम) अधिक आयरन (40.0 पीपीएम)

गेहूंः एचपीबीडब्ल्यू 01 आयरन (40.0 पीपीएम) एवं जिंक (40.6 पीपीएम)

मक्काः पूसा विवेक क्यूपीएम 9 उन्नत : प्रो– विटामिन–ए (8.15 पीपीएम), लायसीन (2.67%) एवं ट्रिप्टोफेन (0.74ः)

मक्काः पूसा एचएम 4 उन्नतः ट्रिप्टोफेन (0.91%) एवं लायसीन (3.62%)

मक्काः पूसा एचएम 8 उन्नत : ट्रिप्टोफेन (1.06%) एवं लायसीन (4.18%)

मक्काः पूसा एचएम 9 उन्नत : ट्रिप्टोफेन (0.68%) एवं लायसीन (2.97%).

बाजराः एचएचबी 299ः आयरन (73.0 पीपीएम) एवं जिंक (41.0 पीपीएम)

बाजराः एएचबी 1200ः आयरन (73.0 पीपीएम)

मसूरः पूसा अगेती मसूर : आयरन (65.0 पीपीएम)

सरसोंः पूसा डबल जीरो 31ः इरूसिक एसिड <2.0 प्रतिशत एवं ग्लूकोसिनोलेट <3.0 पीपीएम

सरसोंः पूसा सरसों 30ः इरूसिक एसिड <2.0 प्रतिशत

फूलगोभीः पूसा बीटा केसरी 1ः बीटा कैरोटिन 8.0 – 10.0 पीपीएम

शकरकंदः भू सोना : अधिक बीटा कैरोटिन (14.0 मि ग्रा./100ग्रा.)

शकरकंदः भू कृष्णा : एंथोसायनिन (90.0 मि ग्रा./100ग्रा.)

अनारः सोलापुर लाल : अधिक आयरन (5.6– 6.1 मिग्रा./100ग्रा.), जिंक (0.64–0.69 मिग्रा./100ग्रा.) एवं विटामिन सी (19.4–19.8 मिग्रा./100ग्रा.)

प्रजनक बीज उत्पादन

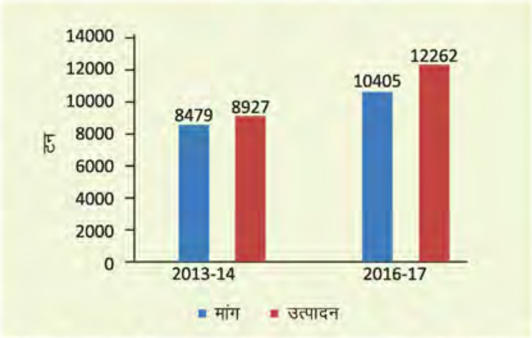

अधिकांश फसलों में प्रजनक बीज का उत्पादन मांग से अधिक था

प्रजनक बीज उत्पादन

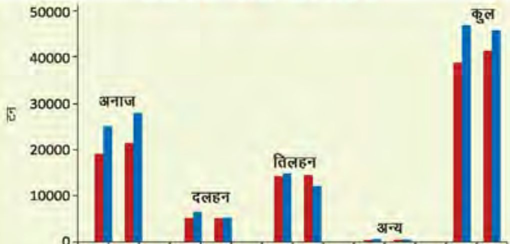

	अनाज 2009-10 to 2012-13	अनाज 2013-14 to 2016-17	दलहन 2009-10 to 2012-13	दलहन 2013-14 to 2016-17	तिलहन 2009-10 to 2012-13	तिलहन 2013-14 to 2016-17	अन्य 2009-10 to 2012-13	अन्य 2013-14 to 2016-17	कुल 2009-10 to 2012-13	कुल 2013-14 to 2016-17
मांग (टन)	18070	20292	4876	4809	13502	13646	352	451	36800	39192
उत्पादन (टन)	23682	26436	6151	4985	14036	11462	570	512	44440	43595

वर्तमान चार वर्षों एवं पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान फसल–वार प्रजनक बीज की मांग एवं उत्पादन

बागवानी फसलों की जारी की गई किस्में

फसलें	विकसित किस्में	फसलें	विकसित किस्में
फल	10	लहसून	8
सब्जी	78	मसाले	14
पुष्प	3	नारियल	7
आलू	2	कन्द	2
प्याज	11	काजू	1

सेब के अधिक उत्पादन हेतु सघन रोपण विधि

सघन रोपण: 2.5 मी × 2.5 मी।

आधुनिक टरी ट्रेनिंग (मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम) और परंम्परागत वार्षिक प्रूनिंग विधि का उपयोग।

टपक सिंचाई: संस्तुतित उर्वरक एवं खाद संरक्षित कृषि के लिए उपयोगी।

उपज में चार गुणा से अधिक वृद्धि (7.5 टन/है के मुकाबले 30–35 टन/है)।

बागवानी में चुनिंदा नई किस्में

मेदिका–एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर अंगूर

उच्च एंटी ऑक्सीडेंट मात्रा तथा जूस के लिए उपयुक्त मेदिका अंगूर (लाल गुलाबी)।

अमरूद हाइब्रिड अर्का किरण

फल का वजनः 200–220 ग्राम
लाइकोपिन की उच्च मात्राः 6–7 एमजी/100 ग्रम मुलायम बीज
उपजः 30 से 35 टन/है.

काजू हाइब्रिड (एच–126) :

जम्बो नट (11–12 ग्राम प्रति नट), बड़ा आकार होने से निर्यात के लिए उपयुक्त।

धनिया अजमेर कोरियंडर–1

बीज उत्पादन एवं हरी सब्जी के लिए उपयुक्त
बीज की अधिक उपजः 12.5 क्विटंल/है.
अवधिः 150–152 दिन
स्टेप गाल प्रतिरोधी

पूर्व विकसित मेगा किस्मों से अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति

- भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा विकसित गन्ने की उन्नत किस्म Co–0238 (12% शर्करा) का रकवा उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती राज्यों में 14.75 लाख हैक्टर तक पहुंच चुका है। इस किस्म से प्रचलित किस्मो की अपेक्षा 1.5 से 2 प्रतिशत अधिक शर्करा की प्राप्ति होती है। पिछले चार वर्षों में अकेले इस किस्म की वजह से किसानों एवं गन्ना मिल चालको की आय में प्रचलित किस्मों की अपेक्षा 6550.00 करोड़ रु. की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई।
- गेहूं की मुख्य किस्म HD 2967 की खेती वर्तमान में पूरे देश में 10 मिलियन हैक्टर से भी अधिक क्षेत्र में की जा रही है ओर इसके प्रजनक बीजों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जो कि 2017–18 के दौरान 3600 क्विंटल तक पहुंच गई जो भारतीय कृषि के इतिहास में किसी एक प्रजाति की अभी तक की सबसे बड़ी मांग है।
- भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली द्वारा विकसित बासमती चावल की उल्लेखनीय किस्म, पूसा बासमती 1121 के निर्यात से वर्ष 2014 से 2017 के दौरान देश को 71900 करोड़ रु. के बराबर विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई जो वर्ष 2011–14 (62800 करोड़ रु.) की तुलना में 9,100 करोड़ रुपये (14.50 प्रतिशत) अधिक है।
- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू द्वारा विकसित टमाटर की किस्म अर्का रक्षक जो कि पर्ण कुंचन वायरस, जीवाण्विक मुरझान एवं अगेता झुलसा के लिए प्रतिरोधी है, ने 120 टन प्रति हेक्टेयर की उपज क्षमता के साथ बाजार में उपलब्ध सभी वाणिज्यिक संकरों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस किस्म का प्रसार देश भर में हुआ है, 27 राज्यों में 20,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में इसे उगाया जा रहा है। जिससे किसानों को पिछले 4 वर्षों में 400 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हुई है।

प्रयोगशाला से खेत तकः प्रमुख पहलें

किसानों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, बीज उत्पादन एवं मृदा परीक्षण

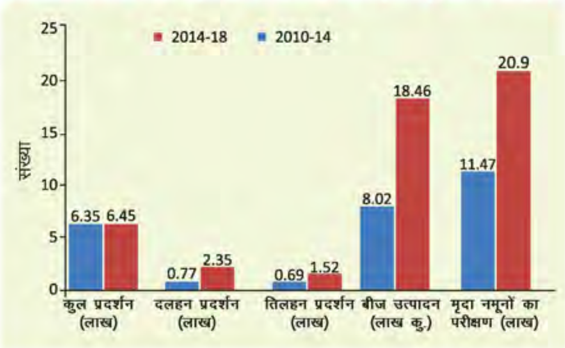

किसानों के खेत पर परीक्षण एवं प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा बीज, रोपण सामग्री एवं पशुधन/मछली बीज उत्पादन

केवीके द्वारा कार्यान्वित ऑन फार्म परीक्षण	1.32 लाख
केवीके द्वारा कार्यान्वित अग्रमपंक्ति प्रदर्शन	5.04 लाख

प्रशिक्षित किसान	53.96 लाख
प्रशिक्षित प्रसार कर्मी	5.62 लाख

प्रसार कार्यक्रमों में 540.04 लाख किसानों की भागीदारी

केवीके द्वारा बीज का उत्पादन एवं वितरण	184600 टन
रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण	1711.91 लाख

उत्पादित पशुधन एवं मछली बीज (संख्या)	950.22 लाख
मृदा, जल, पौधा, उर्वरक नमूनों का परीक्षण (संख्या)	20.90 लाख

किसानों को प्रदान किए गए मोबाइल एग्रो–एडवायजरी की संख्या: 1022.67 लाख

युवाओं को कृषि की तरफ आकर्षित कर उनकी अभिरुचि बनाए रखना (आर्या)

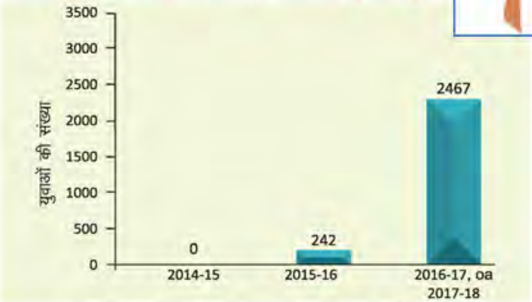

इसके अन्तर्गत 2467 ग्रामीण युवा लाभान्वित हुए

फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत समग्र ग्राम विकास हेतु कृषि मॉडल

इसके अन्तर्गत 48291 किसान परिवार को कवर करते हुए भाकृअप संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 51 केन्द्रों द्वारा कार्यान्वयन

मेरा गाँव मेरा गौरव

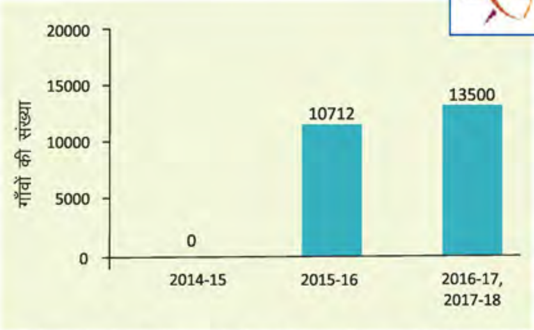

मेरा गाँव मेरा गौरव परियोजना में वैज्ञानिक दलों द्वारा 13500 गांवों में कार्य

नवीन आईसीटी (सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी) ऐप्स एवं पोर्टल

विगत चार वर्षों में भाकृअनुप के अनुसंधान संस्थानों द्वारा विभिन्न कृषि तकनीकियों, पशुधन प्रबंधन, मत्स्य प्रबंधन आदि विषयों पर 130 से अधिक तकनीकी एप्स विकसित किए गए हैं।

जय किसान जय विज्ञान

नए आईसीएआर पुरस्कार स्थापित

पुरस्कार का नाम (संख्या)	शुरूआत का वर्ष	पुरस्कार का मूल्य
1) आईसीएआर प्रशासनिक पुरस्कार (तकनीकी, प्रशासनिक एवं सहायक श्रेणियों में प्रत्येक के लिए 3 पुरस्कार)	2014	प्रत्येक को रु. 51000/–
2) हलधर जैविक किसान पुरस्कार (1)	2015	रु. 1,00,000/–
3) पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार (1 राष्ट्रीय एवं 11 क्षेत्रीय पुरस्कार)	2016	राष्ट्रीय : रु. 1,00,000/– क्षेत्रीय : रु. 51000/– प्रत्येक
4) पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार (1 राष्ट्रीय तथा 11 क्षेत्रीय पुरस्कार)	2016	राष्ट्रीय : रु. 25,00,000/– क्षेत्रीय : रु. 2,25,000/– प्रत्येक

जलवायु अनुकूलनशीलता और टिकाऊ कृषि उत्पादकता हेतु पहलें

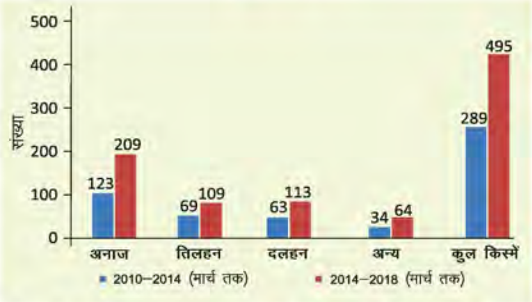

जारी की गई जलवायु अनुकूलन किस्मों की संख्या जो अजैविक कारकों के प्रति सहिष्णु/प्रतिरोधक हैं

विकसित किए गए एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल (आईएफएस) की संख्या

जिला आकस्मिक योजना

जैविक खेती के लिए विकसित की गई कृषि तकनीकियों के पैकेज

जैविक खेती की इन तकनीकियों को देश भर के 20 राज्यों, जिनमें पूर्वोत्तर के भी सभी राज्य शामिल हैं, में जैविक खेती पर समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के केन्द्रों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों के खेत में प्रदर्शित किया जा रहा है।

केवीके द्वारा 151 जलवायु अनुकूल गांव स्थापित किए गए

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि–सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एक साथ मिलकर देश भर में 100 जलवायु अनुकूल एकीकृत कृषि प्रणालीयों हेतु प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना करने के लिए कार्य कर रहे है।

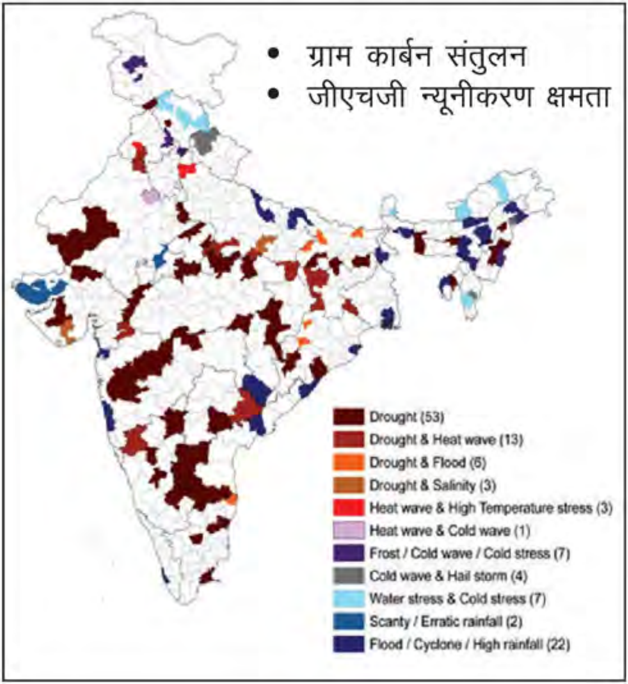

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा (नई दिल्ली) में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय फिनोमिक्स (National Phenomics Facility) का लोकार्पण

माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय फिनोमिक्स सुविधा समर्पित की। यह सुविधा फसल विज्ञान सहित कृषि में नवीनतम अनुसंधानों को बढ़ावा देने के अलावा विभिन्न कृषि फसलों पर बदलते हुए जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करने में वरदान सिद्ध होगी।

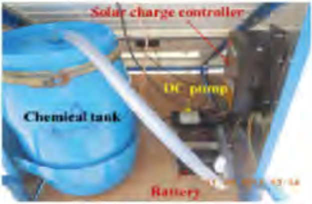

सौर कृषि प्रणाली में कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए सोलर पीवी स्प्रेयर का विकास

एग्रौ–वोल्टैक सिस्टम/सौर कृषि (सोलर फार्मिंग)

एग्री–वोल्टेक सिस्टम

जमीन के एक टुकड़े से एक ही साथ पीवी माड्यूल के जरिए फसल उगाना तथा बिजली पैदा करना

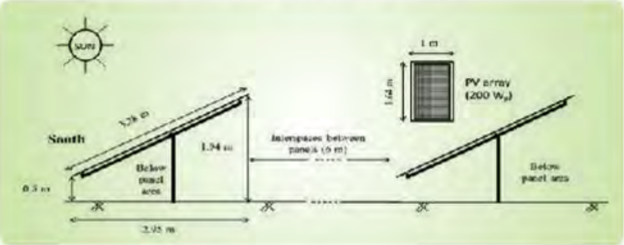

मॉडल क्षेत्र: 1 हेक्टेयर

सौर पीवी सृजन क्षमता: 0.5 मेगावाट, प्रतिदिन बिजली सृजन: 2500 किलोवाट प्रति घंटे, निवेश: 2.5 करोड़ रुपये, बिजली से आय सृजन: लगभग 45 लाख रुपये वार्षिक, प्रणाली की आयु: 25 वर्ष, लागत रिकवरी का समय: 7 वर्ष, मूंग उपज: 4.0 क्वि./हेक्टेयर

फसल अवशेषों को जलाने से रोकने में केवीके की पहलें

भाकृअप की कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के साथ साझेदारी से

- 35 केवीके द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया
- 45000 किसानों को प्रोत्साहित किया गया
- डीडी किसान चैनल पर विशेष वाद–संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया
- हैप्पी सीडर, शून्य जुताई मशीन, अवशेषों की मशीन द्वारा पुलिया बनाना एवं बांधना एवं अन्य अवशेष प्रबंधन क्रियाओं पर 4708 हैक्टेयर क्षेत्र में 1200 सीधा प्रदर्शन संचालित किए गए

पंजाब एवं हरियाणा में विगत दो वर्षों के दौरान फसल अवशेषों को जलाने का सैटेलाइट चित्रण द्वारा आकलन

पंजाब 2016

पंजाब 2017

हरियाणा 2016

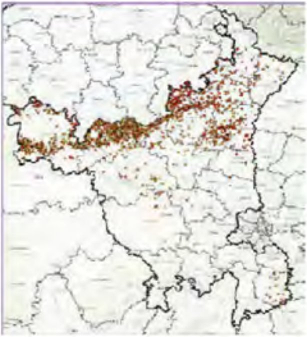

हरियाणा 2017

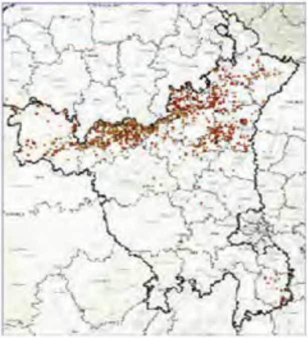

निगरानी अवधिः 10–अक्तूबर से 14–नवंबर

जिला आकस्मिक योजना

प्रतिकूल जलवायु के कृषि पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के समाधान हेतु जिला स्तरीय आकस्मिकता योजनाऐं

प्रतिकूल जलवायु के कृषि पर विपरीत प्रभाव के समाधान हेतु जिला स्तरीय आकस्मिकता योजना

जैविक खेती के लिए विकसित की गई कृषि तकनीकियों के पैकेज

वर्ष 2014–18 की अवधि में कुल विकसित जैव तकनीकों की संख्या 33 जो पिछले चार वर्षों की तुलना में 83.3 प्रतिशत अधिक है।

आय और पोषणिक सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक कृषि प्रौद्योगिकियां

कुक्कुट की 4 घरेलू प्रजातियां विकसित और जारी की गईं

किसानों और विकास एजेंसियों को दिए गए पौल्ट्री सीड (चूजे)

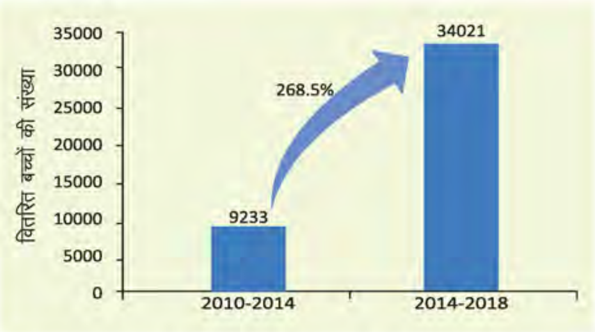

विकास एजेंसियों एवं किसानों को शूकर की उन्नत नस्लों के बच्चों (Piglets) का वितरण

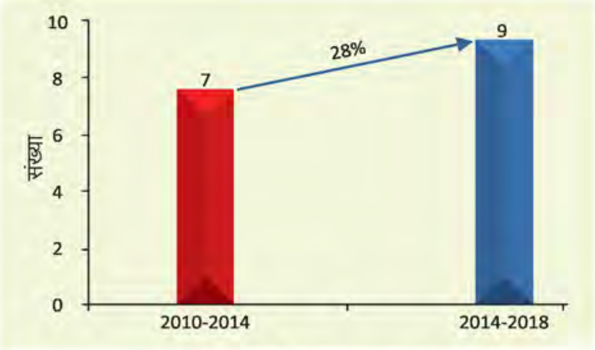

विकसित टीकों की संख्या

भैंस क्लोनिंग में सफलता की कहानियां

लालिमाः श्रेष्ठ मुर्रा नस्ल की भैंस से उत्पन्न मादा क्लोन्ड कटड़ी।

रजतः कई वर्ष पूर्व मृत उच्च दर्जे वाले संतति परीक्षित मुर्रा सांड (एमयू–4393) के फ्रोज़न वीर्य से एक नर कटड़ा की क्लोनिंग।

दीपाशाः छत्तीसगढ़ राज्य में लुप्तप्राय वन्य भैंस की एक क्लोन्ड मादा कटड़ी।

रजत

दिपाशा

मछली प्रजनन प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया

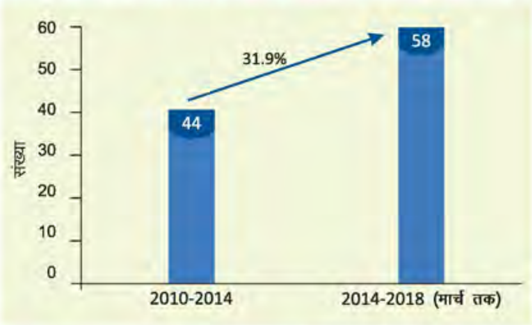

मछली के उत्पाद और मत्स्यन क्राफ्ट तथा गियर को डिजाइन किया गया

मछली आहार विकसित किया गया

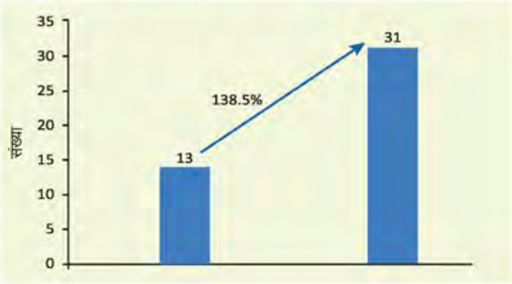

समुद्री पिंजरों का प्रदर्शन

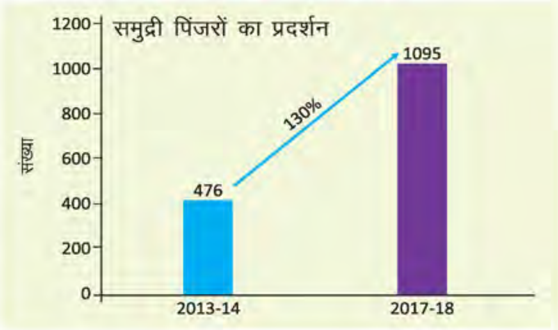

भारत से खोजी गई मछली की प्रजातियों का लक्षण–वर्णन और उनसे पोषक औषधीय पदार्थों का विकास

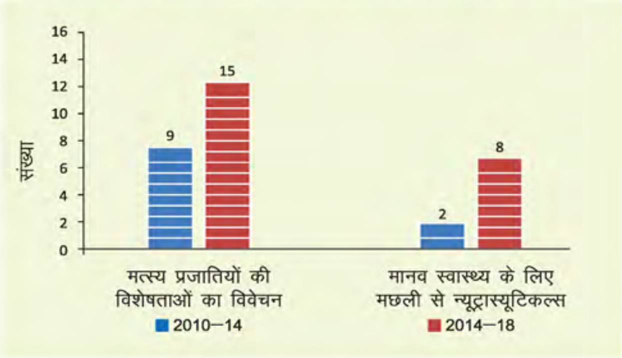

कार्य–क्षमता बढ़ाने एवं लागत कम करने के लिए स्वदेशी मछली आहार संरचना विकसित की गई

जलीय जीवों से पोषक औषधीय पदार्थों (न्यूट्रास्यूटिकल्स) का विकास

मानव स्वास्थ के लिए विभीन्न उच्च मूल्य के यौगिक एवं न्युट्रास्युटिकल तैयार किये गए तथा उनका वाणिज्यीकरण भी किया गया, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- दर्द एवं अर्थराइटिस के लिए–ग्रीन मसल अर्क (कडलमीन™ जीएमई), ग्रीन शैवाल अर्क (कडलमीन™ जीएई)
- समुद्री खरपतवार एंटीडाइबेटिक अर्क (कडलमीन™ एडीई)–टाइप–2 डाइबेटीज के लिए एक ग्रीन औषधि
- समुद्री खरपतवार मोटापा–रोधी अर्क (कडलमीन™ एसीई)–मोटापा/डिसलिपिडेमिआ को रोकने के लिए एक न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद
- सूक्ष्मपोषक तत्व बढ़ाने के लिए– समुद्री खरपतवार न्यूट्रास्यूटिकल पेय 'न्यूट्रिड्रिंक'

स्टार्ट–अप/कृषि–उद्यमियों को भाकृअप की सहायता

भाकृअप ने 25 संस्थानों में स्थापित एग्री–बिजनेस इनक्यूबेशन केंद्रों के एक नेटवर्क में प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन कार्यकलाप तथा टेक्नो–उद्यमियों को शिक्षित बनाने के लिए एक मजबूत सहायता तंत्र विकसित किया है। भाकृअप के संस्थान देश भर में 194 स्टार्ट–अप/कृषि उद्यमियों की सहायता कर रहे हैं। इन कृषि–उद्यमियों/स्टार्ट–अप कंपनियों में से 17 कंपनियों ने 19 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति भवन में नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता (एफआईएनई) समारोह में भाकृअप संस्थानों के संपूर्ण सहयोग से अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया।

उत्पादन लागत कम करने, कृषि आय में सुधार लाने और कठिन परिश्रम को कम करने के लिए अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकियां

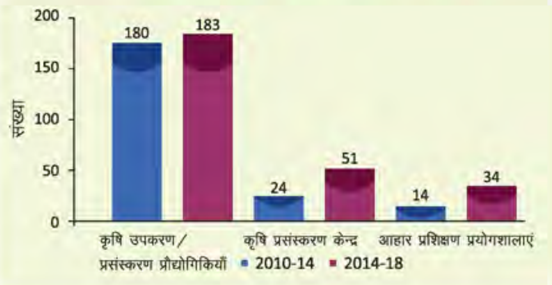

किसानों की आय
दोगुनी करने के लिए कार्यनीति

सात सूत्री कार्यनीति

माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है अर्थात् वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सात सूत्री कार्यनीति का समर्थन भी किया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सात सूत्री कार्यनीति :–

1 "प्रति बूंद अधिक फसल" प्राप्त करने के उद्देश्य से पर्याप्त बजट के साथ सिंचाई पर विशेष जोर देना।

2 प्रत्येक खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पर आधारित गुणवत्तायुक्त बीजों एवं पोषक तत्वों का प्रावधान करना।

3 फसल पश्चात हानियों को रोकने के लिए भंडारगारों एवं कोल्ड चेन के निर्माण में अत्यधिक निवेश करना।

4 खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना।

5 राष्ट्रीय कृषि मण्डी का सृजन, विसंगतियों का निराकरण और 585 मंडियों में ई–प्लेटफार्म की स्थापना।

6 उचित कीमत पर जोखिमों को कम करने के लिए नई फसल बीमा स्कीम को शुरू करना।

7 कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसे सहायक क्रियाकलापों को बढावा देना।

किसानों के लिए ज्यादा लाभार्थ तारतम्य बैठाने के लिए सरकार की विभिन्न स्कीमें :

1. उत्पादकता लाभ के माध्यम से उच्च उत्पादन के लिए:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) – मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, पोषक तत्वों से युक्त मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें।
- बागवानी समेकित विकास मिशन (एमआईडीएच) –बागवानी फसलों की उच्च वृद्धि दर।
- तिलहन और ऑयलपाम के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी) –तिलहन और ऑयलपाम के उत्पादन में वृद्धि के लिए एनएमओओपी (वर्ष 2014–15 में शुरू किया गया)।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन – स्वदेशी पशु और भैंसों के जीन पूल के विकास और बढ़ी हुई उत्पादकता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (दिसंबर 2014 में शुरू किया गया)।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन – राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014–15 में शुरू की गई। पशुधन, विशेष रूप से छोटे पशु (भेड़/बकरी, मुर्गी आदि) एवं गुणवत्ता वाले फीड और चारा की पर्याप्त उपलब्धता के साथ–साथ विकास सुनिश्चित करने के लिए।
- निली क्रांति–समेकित इन लैंड तथा समुद्री मत्स्य पालन संसाधनों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2015 में मत्स्य पालन विकास के लिए ''नीली क्रांति'' स्कीम की घोषणा की।

माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों की आय में सुधार के लिए चार पहलुओं का उल्लेख किया है, जैसे (1) इनपुट लागत को कम करना, (2) उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना, (3) अपव्यय को कम करना और (4) आय के वैकल्पिक स्रोत तैयार करना।

2. खेती की लागत में कमी के लिए

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) (2 साल चक्र)– उर्वरक का समझदारी से और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग को नियमित करने, फसल में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने तथा अनावश्यक उर्वरक अनुप्रयोग की लागत कम करने के लिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) – सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में स्थायी समाधान मुहैया कराने के लिए जिसमें जल स्रोत वितरण नेटवर्क और खेत स्तर पर अनुप्रयोग शामिल हैं, 'हर खेत को पानी' आदर्श वाक्य के साथ सूक्ष्म सिंचाई घटक (1.2 मिलियन हेक्टेयर/वार्षिक लक्ष्य रखा है)।
- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) – जैविक खेती को बढ़ावा

देने के लिए एवं इससे मृदा स्वास्थ्य तथा जैविक अंश बेहतर होंगे। इससे किसान की कुल आमदनी बढ़ेगी तथा बेहतर मूल्य मिलेगा।

3. लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए

- राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई–नाम)
- किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर लाभ दिलाने के लिए वास्तविक समय के अनुसार बेहतर मूल्य डिस्कवरी, पारदर्शिता लाकर और प्रतियोगिता का स्तर सुनिश्चित करके कृषि बाजार में क्रांति लाने के लिए यह स्कीम एक नवीन मार्किट प्रक्रिया है। इससे ''एक राष्ट्र एक बाजार'' की ओर बढेंगे।
- एक नया मॉडलः कृषि उत्पाद एवं पशुधन मार्किटिंग (उन्नयन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2017 को 24 अप्रैल, 2017 में जारी किया गया है। इसमें निजी मार्किट स्थापित करने, सीधी मार्किटिंग, किसान उपभोक्ता मार्किट, विशेष वस्तु मार्किट, वेअरहाउस कोल्ड स्टोरेज या ऐसी किसी इमारत को मार्किट सब यॉर्ड्स के तौर पर घोषित करने संबंधी प्रावधानों को शामिल करके इसे राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकार किया जाना है।
- वेयरहाउसिंग की व्यवस्था तथा फसल के बाद कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना ताकि किसान को मुसीबत में अपना उत्पादन न बेचना पड़े तथा नेगोशिएबल रिसीट के लिए अपने उत्पाद को वेयरहाउस में रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कुछ फसलों के लिए अधिसूचित किया गया है।
- संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत तिलहन, दालों तथा कपास की खरीद केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है।
- मार्किट इन्टरवेन्सन स्कीम (एमआईएस) उन कृषि एवं बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए है जो नाशीवंत प्रकृति के हैं और जिन्हें पीएसएस के तहत कवर नहीं किया गया है।

4. जोखिम प्रबंधन एवं सतत प्रक्रियाएं

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एवं पुर्न संरचित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आर डब्ल्यू सी आई एस) फसल चक्र के सभी चरणों में बीमा कवर उपलब्ध कराता है। इसमें कुछ निर्धारित मामलों में फसल आने के बाद के जोखिम भी शामिल हैं और ये बहुत कम प्रीमियम दर पर किसानों को उपलब्ध हैं।
- पूर्वोत्तर में मिशन आर्गेनिक खेती (एमओवीसीडी–एनई) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती की क्षमता को देखते हुए यह मिशन शुरू किया गया है।

5. संबद्ध क्रियाकलाप

- फसल के साथ, खेती की जमीन पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए "हर मेढ़ पर पेड़" स्कीम वर्ष 2016–17 में शुरू की गई। यह स्कीम उन राज्यों में लागू की जा रही है जिन्होंने इमारती लकड़ी ले जाने के लिए परिवहन नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
- राष्ट्रीय बांस मिशनः कृषि आय के अनुपूरक के रूप में, इस क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला आधारित समग्र विकास के लिए केन्द्रीय बजट 2018–19 में राष्ट्रीय बांस मिशन की घोषणा की गई है।
- मधुमक्खी पालनः किसानों की आय एवं फसलों की उत्पादकता और शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरूआत की गई।
- डेयरीः डेयरी विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण स्कीमें है– राष्ट्रीय डेयरी योजना–1 (एनडीपी–1), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम।
- मात्स्यिकीः मात्स्यिकी क्षेत्र में अपार संभावना को देखते हुए जमीन और समुद्रीय दोनों जगहों पर मछली उत्पादन पर विशेष जोर देने वाली बहुआयामी गतिविधियों के साथ "नीलीक्रांति" कार्यान्वित की जा रही है।

6. कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के पुनरूद्धार अर्थात् आरकेवीवाई–रफ्तार के रूप में तीन वर्षों तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है जिसका उद्देश्य कृषि व्यवसाय को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास के साथ–साथ बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से लाभकारी आर्थिक गतिविधि के रूप में बनाना है। नए दिशा–निर्देश कृषि–उद्यम और इंक्यूबेशन सुविधाओं को बढ़ावा देने के अलावा उत्पादन व उत्पादनोंपरांत आधारभूत सुविधा के निर्माण के लिए अधिक आवंटन उपलब्ध कराते हैं।

7. ऑपरेशन ग्रीन

- टमाटर, प्याज और आलू ऐसी बुनियादी सब्जियां हैं जिन्हें पूरे वर्ष के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तथापि जल्द खराब होने वाली मौसमी और क्षेत्रीय जिन्सों से किसानों और उपभोक्ताओं को इस प्रकार जोखिम का सामना करना पड़ता है जिससे दोनों ही वर्ग प्रभावित होते हैं। इस दिशा में सरकार ने ''ऑपरेशन फ्लड'' की तर्ज पर ''ऑपरेशन ग्रीन'' को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। ''ऑपरेशन ग्रीन'' से किसान उत्पादक संगठन, कृषि सभार तंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यवसायिक प्रबंधन से जुड़े कार्यों का संवर्धन होगा।

8. प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

- भारत सरकार ने 14 वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुरूप 3 मई 2017 को 2016–20 की अवधि के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम – प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (कृषि–समुद्रीय प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण समूह विकास स्कीम) को मंजूरी दी है। इस स्कीम का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ।
- प्रधान मंत्री किसान सम्पादा योजना: एक व्यापक पैकेज है जिसके तहत खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ

आधुनिक अवसंरचनाएं सृजित होगी।

- प्रधानमंत्री किसान सम्पाद योजना के तहत निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है
- मेगा फूड पार्क।
- समेकित शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना।
- खाद्य प्रसंस्करण का सृजन/निर्माण एवं क्षमताओं का संरक्षण।
- कृषि प्रसंस्करण समूह अवसंरचना।
- पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संबंधों की स्थापना।
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना।
- मानव संसाधन एवं संस्थाओं का विकास।

9. कृषि में पूंजीगत निवेश

कृषि और संबद्व क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कोष निधिः

1. एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्क्चर फंड के द्वारा ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करना प्रस्तावित है।
2. देश में सूक्ष्म सिंचांई को बढावा देने के लिए माइक्रो सिंचाई फंड।
3. मरीन मत्यसिकी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार, सहकारी समितियों, व्यक्तिगत उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्क्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) का निर्माण किया गया है।
4. डेयरी प्रसंस्करण और इन्फ्रास्ट्क्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ) कुशल दूध खरीद प्रणाली के निर्माण के लिए ग्रामीण स्तर पर प्रसंस्करण और शीतल बुनियादी ढांचे की स्थापना।
5. समेकित भेड़, बकरी, सुअर और कुक्कुट विकास कोषः उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कुट के एकीकृत विकास, मुर्गी पालन के आधुनिकीकरण और बकरी, भेड और सूअर के लिए जिला स्तर पर सीमेन केन्द्रों की स्थापना एवं सुद्दढीकरण।

कृषि एवं वानिकी पर
चौथी आसियान-भारत मंत्री-स्तरीय बैठक

कृषि एवं वानिकी संबंधी चौथी आसियान-भारत मंत्री स्तरीय बैठक 12 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली, भारत में हुई और सतत सहयोग के लिए कृषि एवं वानिकी के क्षेत्र में हमारी भावी पहलों के लिए आगे के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ।

Printed by: Royal Offset Printers # 9811622258

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार